सिर्फ दर बढ़ने से नहीं होगा विकास

भल्ला और अहलूवालिया ने 2047 के लक्ष्य पर किया आगाह, लंबे समय तक ऊंची विकास दर बनाए रखने पर जोर

- पहली तिमाही में 7.8% रही विकास दर
- 2047 तक विकसित बनने के लिए मौजूदा रफ्तार

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 8 सितंबर. भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की मजबूत विकास दर दर्ज कर वैश्विक चुनौतियों के बीच अपनी मजबूती दिखाई है.

हालांकि, दो प्रमुख अर्थशास्त्रियों सुरजीत भल्ला और मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने स्पष्ट किया है कि यह रफ्तार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है. दोनों का मानना है कि भारत को लंबे समय तक इससे कहीं अधिक तेज और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि बनाए रखने की जरूरत होगी. साथ ही केवल सकल घरेलू उत्पाद बढ़ना ही विकसित अर्थव्यवस्था की पहचान नहीं हो सकता. प्रति व्यक्ति आय, रोजगार, निवेश, उत्पादन और विकास का लाभ समाज के व्यापक हिस्से तक पहुंचना भी जरूरी है.

जीडीपी के 7.8 प्रतिशत आंकड़े को लेकर उठे सवालों पर भल्ला और अहलूवालिया ने आंकड़ों में राजनीतिक हेरफेर के आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि नई जीडीपी श्रृंखला में आधार वर्ष, आंकड़ों के स्रोत और गणना की पद्धति में बदलाव हुआ है, इसलिए पुरानी और नई श्रृंखला के आंकड़ों को सीधे मिलाकर विकास दर निकालना उचित नहीं है. हालांकि, अहलूवालिया ने यह भी कहा कि किसी एक तिमाही के आंकड़े के आधार पर पूरे वर्ष की आर्थिक तस्वीर तय नहीं की जा सकती.

भल्ला के मुताबिक 2047 के लक्ष्य के लिए भारत को लंबे समय तक दो अंकों के आसपास विकास दर बनाए रखने की जरूरत होगी. वहीं अहलूवालिया ने माना कि भारतीय अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं के मुकाबले अधिक मजबूत नजर आ रही है, लेकिन ऊंची विकास दर को लगातार बनाए रखने के लिए निजी निवेश, संस्थागत सुधार और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान देना होगा.

विज्ञापन विवाद में विमल कंपनी पहुंची हाईकोर्ट

- शाहरुख, अजय और टाइगर को मिले नोटिस
- महाराष्ट्र एफडीए की कार्रवाई पर उठाए सवाल

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 8 सितंबर. विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर चल रहे विवाद में कंपनी पीबी एग्रो ने अपने ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के बचाव में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है.

कंपनी ने महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से तीनों अभिनेताओं को जारी नोटिस रद्द करने की मांग की है. एफडीए ने अभिनेताओं से विज्ञापन में दिखाए जा रहे विमल इलायची उत्पाद को लेकर सबूत मांगे थे और यह स्पष्ट करने को कहा था कि विज्ञापन प्रतिबंधित पान मसाला या तंबाकू उत्पादों के प्रचार के लिए तैयार किया गया सरोगेट विज्ञापन नहीं है. कंपनी का कहना है कि उसका विज्ञापन पूरी तरह वैध है और देश के सभी संबंधित कानूनों एवं नियमों का पालन करता है.

कंपनी ने अदालत में दलील दी कि 11 अगस्त 2026 को जारी नोटिस केवल अभिनेताओं को भेजे गए, जबकि विज्ञापन से संबंधित वास्तविक कार्रवाई का असर कंपनी के कारोबार पर पड़ेगा.

भारी अस्थिरता के बीच सोने-चांदी में आई चमक

एमसीएक्स पर सोना 1.54 लाख और चांदी 2.41 लाख पार

- सोने में 1,207 रुपये की तेजी, 1,54,025 पहुंचा
- चांदी 2,185 रुपये उछली 2,41,201 रुपये प्रति किलो

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 8 सितंबर. वैश्विक स्तर पर बढ़ती अस्थिरता और अमेरिका-ईरान तनाव के बीच निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के रूप में सोने और चांदी का रुख किया. मंगलवार को घरेलू वायदा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में करीब एक फीसदी तक की तेजी दर्ज की गई.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का 5 अक्टूबर, 2026 का अनुबंध 1,52,818 रुपये प्रति 10 ग्राम की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले बढ़त के साथ 1,53,362 रुपये पर खुला. सुबह 10 बजे तक यह 1,207 रुपये यानी 0.79 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,54,025 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. कारोबार के दौरान सोने ने 1,53,361 रुपये का न्यूनतम और 1,54,125 रुपये प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर छुआ.

सोने की तरह चांदी में भी निवेशकों की खरीदारी जारी रही. एमसीएक्स पर 4 दिसंबर, 2026 का चांदी अनुबंध पिछली क्लोजिंग 2,39,016 रुपये प्रति किलो के मुकाबले 2,40,009 रुपये पर खुला. सुबह 10 बजे तक चांदी 2,185 रुपये यानी 0.91 प्रतिशत की तेजी के साथ 2,41,201 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी. कारोबार के दौरान चांदी ने 2,40,009 रुपये का निचला और 2,41,724 रुपये प्रति किलो का ऊपरी स्तर छुआ.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दोनों कीमती धातुओं में मजबूती रही. सोना हल्की तेजी के साथ करीब 4,478 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ करीब 67.50 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने पर निवेशक अक्सर सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर रुख करते हैं, जिसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर दिखाई दे रहा है.

अमेरिकी टैरिफ की आशंका से तांबा पहुंचा रिकॉर्ड ऊंचाई पर

- एक साल में तांबे के भाव में करीब 47 प्रतिशत उछाल
- खदान उत्पादन में गिरावट से आपूर्ति संकट की चिंता

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 8 सितंबर. अमेरिकी बाजार में रिफाइंड तांबे पर टैरिफ लगाए जाने की आशंका के बीच वैश्विक बाजार में तांबे की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है.

लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) पर तीन महीने के वायदा में तांबे का भाव 0.8 प्रतिशत बढ़कर 14,533 डॉलर प्रति मीट्रिक टन के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया. इससे पहले जनवरी में तांबे ने 14,527.50 डॉलर प्रति मीट्रिक टन का रिकॉर्ड स्तर बनाया था. टैरिफ की आशंका के चलते कारोबारी तांबे की आपूर्ति अमेरिका की ओर मोड़ रहे हैं, जिससे अन्य वैश्विक बाजारों में उपलब्धता घट रही है और कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है. इस साल अब तक तांबे की कीमत करीब 17 प्रतिशत बढ़ चुकी है, जबकि पिछले 12 महीनों में इसमें लगभग 47 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है. घरेलू बाजार में भी तांबे की कीमतों में मजबूती देखी गई.

मेडिकल टूरिज्म : गोयल की पांच सूत्रीय योजना

- केयरगिवर्स के प्रशिक्षण व प्रमाणन पर रहेगा फोकस
- बीमा व हेल्थ-टेक कंपनियां विकसित करें नए उत्पाद

> गोयल ने राज्यों से अस्पतालों और वेलनेस सेंटरों में गुणवत्ता सुधारने, स्वास्थ्य सुविधाओं के नेटवर्क का विस्तार करने और बेहतर सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रभावी प्रचार-प्रसार करने को कहा. गोयल ने जोर दिया कि मेडिकल टूरिज्म का लाभ केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए. छोटे और मझोले शहरों तक सुविधाओं का विस्तार होने से रोजगार, नए अवसर और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा. मंत्री ने विभिन्न देशों से आने वाले मरीजों के लिए अलग-अलग भाषाओं के दुभाषियों का पूल तैयार करने का भी सुझाव दिया.

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 8 सितंबर. देश में मेडिकल टूरिज्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पांच सूत्रीय कार्ययोजना सुझाई है.

उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य और वेलनेस सेवाओं के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम करना होगा. गोयल ने कौशल विकास को इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता बताया. उनके अनुसार, केयरगिवर्स को बेहतर प्रशिक्षण और प्रमाणन देकर ऐसा कुशल कार्यबल तैयार किया जाना चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मरीजों की देखभाल कर सके.

राजधानी में भारत हेल्थ ग्लोबल एक्सपो-2026 के तहत आयोजित 'संजीवनी' कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक अस्पतालों को 'हील इन इंडिया' गेटवे से जोड़ना जरूरी है. अस्पतालों को उपचार पैकेज की जानकारी ईमानदारी, नैतिकता और पारदर्शिता के साथ उपलब्ध करानी चाहिए. उन्होंने चेताया कि किसी अस्पताल की एक गलत गतिविधि भी भारत की स्वास्थ्य सेवाओं की प्रतिष्ठा और वैश्विक भरोसे को नुकसान पहुंचा सकती है. गोयल ने बीमा और हेल्थ-टेक कंपनियों से मेडिकल टूरिज्म को सुविधाजनक बनाने वाले नए उत्पाद और डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने का आह्वान किया. साथ ही, दुनिया के विभिन्न देशों में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी प्रदर्शनियां और प्रस्तुतियां आयोजित करने, मरीजों के लिए सुविधा केंद्र स्थापित करने तथा वैश्विक अस्पतालों के साथ साझेदारी और समझौते करने का सुझाव दिया.

तेल की तेजी से रुपया 10 पैसे फिसला

- शुरुआत में 94.49 पर खुली भारतीय मुद्रा
- सोमवार को 13 पैसे गिरकर 94.56 पर बंद

> कारोबारियों के अनुसार, ब्रेंट कच्चे तेल का भाव बढ़कर 97.61 डॉलर प्रति बैरल पहुंचने से रुपये पर दबाव बढ़ा. हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक की लगातार डॉलर बिकवाली और विदेशी मुद्रा के मजबूत प्रवाह से रुपये की गिरावट सीमित रहने की उम्मीद है.

नवभारत न्यूज नेटवर्क
मुंबई, 8 सितंबर. पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच भारतीय रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे कमजोर होकर 94.66 पर आ गया.

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 94.49 प्रति डॉलर पर खुला, लेकिन बाद में गिरकर 94.66 के स्तर पर पहुंच गयापश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच भारतीय रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे कमजोर होकर 94.66 पर पहुंच गया. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 94.49 पर खुला था. यह 13 पैसे गिरकर 94.56 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था.

शेयर बाजार में गिरावट सेंसेक्स 555 अंक टूटा

नई दिल्ली. भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे कारोबारी दिन गिरावट का सिलसिला जारी रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक नुकसान के साथ बंद हुए। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 555.23 अंक यानी 0.73 प्रतिशत गिरकर 75,577.58 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 579.46 अंक तक टूटकर 75,553.35 अंक के निचले स्तर पर पहुंच गया था। वहीं, पचास शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 144.05 अंक यानी 0.61 प्रतिशत गिरकर 23,635.10 अंक पर बंद हुआ.

पीएफ में नहीं डाला पैसा फिर भी मिलेगा ब्याज

3 साल बाद ब्याज बंद होने की बात पूरी तरह सही नहीं

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 8 सितंबर. पीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर अक्सर यह भ्रम रहता है कि नौकरी छोड़ने या खाते में योगदान बंद होने के तीन साल बाद ब्याज मिलना बंद हो जाता है.

हालांकि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के अनुसार यह बात हर सदस्य पर लागू नहीं होती. मौजूदा व्यवस्था में पात्र पीएफ खाते पर सदस्य के 58 साल की उम्र तक ब्याज मिल सकता है. ऐसे में यदि किसी व्यक्ति ने नौकरी छोड़ दी है और उसका पीएफ पैसा खाते में ही जमा है, तो केवल तीन साल तक योगदान नहीं होने के आधार पर ब्याज मिलना बंद नहीं माना जाएगा. उदाहरण के तौर पर 40 साल की उम्र में नौकरी छोड़ने वाले व्यक्ति को केवल तीन साल बाद ब्याज से वंचित नहीं किया जाएगा. इसी तरह 50 साल की उम्र में नौकरी छोड़ने वाले सदस्य को भी 58 साल की उम्र तक ब्याज मिलने का प्रावधान बताया गया है.

तीन साल से जुड़ा नियम पीएफ खाते के निष्क्रिय होने की स्थिति से संबंधित है. ईपीएफओ के मुताबिक, सदस्य के सेवानिवृत्त होने, स्थायी रूप से देश छोड़ने या मृत्यु के बाद 36 महीने तक खाते में कोई योगदान नहीं आने पर खाते को निष्क्रिय माना जाता है. इसका अर्थ यह नहीं है कि हर ऐसे खाते पर तीन साल बाद ब्याज स्वतः बंद हो जाता है. पीएफ खाते में जमा राशि पर लागू नियमों के अनुसार ब्याज का प्रावधान अलग है. पीएफ खाताधारकों के लिए कर से जुड़े नियमों को समझना भी जरूरी है.

> पीएफ पर मिलने वाला ब्याज हर स्थिति में पूरी तरह करमुक्त नहीं होता. आयकर नियमों के तहत निर्धारित सीमा से अधिक योगदान से जुड़े ब्याज पर कर देनदारी बन सकती है. इसलिए नौकरी छोड़ने के बाद खाते में जमा पूरी राशि पर मिलने वाले ब्याज को सीधे करयोग्य मानना भी सही नहीं होगा. कर का निर्धारण योगदान की प्रकृति और उस पर लागू मौजूदा आयकर नियमों के आधार पर किया जाता है.

समाचार विशेष

खुश नहीं हैं पुराने भाजपा नेता

कोलकाता, 8 सितंबर. पश्चिम बंगाल की एक खास राजनीतिक संस्कृति है, जो शायद देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं है। वहां जो भी हार कर सत्ता से बाहर होता है उसके खिलाफ ऐसा माहौल बनता है, जो उसके खत्म होने पर ही शांत होता है.

जैसे कांग्रेस हार कर सत्ता से बाहर हुई तो उसी पूरी तरह से समाप्त किया गया. लेफ्ट जब हारी तो वह भी पूरी तरह से खत्म हुई और अब ममता बनर्जी की पार्टी हारी है तो उसके साथ भी वैसा ही हो रहा है. पूरी तरह से खत्म करने में कोई तरह के काम होते हैं. पार्टी टूटती है, विधायक व सांसदों के साथ साथ पार्टी का कैडर सत्तारूढ़ दल के साथ जाता है, हारने वाले के ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई होती है और शारीरिक हमले भी होते हैं.

माना जा रहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो यह संस्कृति बदलेगी. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है. पिछले दिनों तृणमूल के महासचिव अभिषेक बनर्जी के के कैमक स्ट्रीट स्थित ऑफिस के ऊपर लगे होर्डिंग को हटाने की एजेंसियां पहुंची थीं. उस दौरान दोनों पक्षों में टकराव हुआ. अब राज्य सरकार ने फायर सेफ्टी का हवाला देकर ऑफिस खाली करने को कहा है.

> ## संस्कृति के हिसाब से काम
> जानकार सूत्रों का कहना है कि भाजपा के पुराने नेता ऐसी बातों को लेकर सहज नहीं हैं. उनका कहना है कि चूंकि तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आए नेता शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं इसलिए वे अब भी उसी संस्कृति के हिसाब से काम कर रहे हैं. वे पुरानी पार्टी से बदला लेने की भावना से काम कर रहे हैं. लेकिन यह भी हकीकत है कि भाजपा का कोई बड़ा नेता उनको रोक भी नहीं रहा है.

महिला आरक्षण बिल के लिए विशेष सत्र की तैयारी!

सरकार किसी भी समय दोबारा बुला सकती है सदन की बैठक

नई दिल्ली, 8 सितंबर. महिला आरक्षण और परिसीमन का मामला देश की राजनीति में एक बार फिर गरमाने वाला है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार सितंबर महीने में संसद का एक विशेष सत्र बुलाने पर गंभीरता से विचार कर रही है.

माना जा रहा है कि यह महत्वपूर्ण सत्र केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने वाले संभावित फेरबदल से ठीक पहले आयोजित किया जा सकता है. आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र की बैठकें खत्म हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इस सत्र के औपचारिक समापन (सत्रवासन) का ऐलान नहीं हुआ है. तकनीकी रूप से सत्र के जीवित होने के कारण सरकार बिना नया समन जारी किए किसी भी समय सदन की बैठक दोबारा बुला सकती है.

संसद के इस विशेष सत्र का समय अभी आधिकारिक रूप से तय नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सितंबर के तीसरे हफ्ते को इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प माना जा रहा है. संभावित तिथियां 18 से 19 सितंबर बताई जा रही हैं. सूत्रों ने जानकारी दी है कि यह प्रस्तावित बैठक तीन से चार दिनों तक चल सकती है. इस सत्र का मुख्य एजेंडा परिसीमन से जुड़े महिला कोटा कानून (महिला आरक्षण विधेयक) को नए सिरे से आगे बढ़ाना होगा. भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय सबसे बड़ी परीक्षा आगामी राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं. साल 2027 की शुरुआत में गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं.

> ### महिला आरक्षण पर फिर सियासी घमासान
> महिला आरक्षण अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक कदम है, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ देने के बाद यह देश के संघीय ढांचे और चुनावी गणित का एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बन गया है. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सीटें बढ़ना और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें तय होना, दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों की टिकट वितरण रणनीति को पूरी तरह बदल देगा.

चुनाव तैयारी | कांग्रेस के गढ़ में सेंध की तैयारी; भाजपा के सामने आई बड़ी नई चुनौती

ट्राइबल बेल्ट में बीएपी की बढ़ती ताकत

जयपुर, 8 सितंबर. राजस्थान के निकाय चुनाव इस बार सिर्फ नगर निकायों की सत्ता का चुनाव नहीं हैं. दक्षिण राजस्थान के आदिवासी बेल्ट में यह चुनाव बदलते राजनीतिक समीकरणों की परीक्षा भी बन गया है.

अलग भील प्रदेश की मांग को लेकर राजनीति करने वाली भारत आदिवासी पार्टी ने इस बार पिछले निकाय चुनाव के मुकाबले करीब तीन गुना ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। पार्टी की बढ़ती सक्रियता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों की चिंता बढ़ा दी है.

बांसवाड़ा-डूंगरपुर लंबे समय से कांग्रेस की मजबूत राजनीतिक जमीन माने जाते रहे हैं. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहां आदिवासी राजनीति का एक अलग राजनीतिक केंद्र तेजी से उभरा है. बीएपी अब इसी प्रभाव को विधानसभा और लोकसभा के बाद नगर निकायों के स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रही है. बीएपी ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की पांच नगर निकायों के 180 वार्डों में से 63 वार्डों में प्रत्याशी उतारे हैं. बांसवाड़ा के 60 में से 20, गढ़ी के 25 में से 11, कुशलगढ़ के 20 में से 6, डूंगरपुर के 40 में से 12 और सागवाड़ा के 35 में से 14 वार्डों में पार्टी चुनाव लड़ रही है. यह संख्या बड़े पैमाने पर स्थानीय चुनावों में असर डालते हुए अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है.

> ### बीएपी का विस्तार कांग्रेस के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती
> दक्षिण राजस्थान में आदिवासी मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से कांग्रेस के साथ रहा है. विधानसभा चुनावों में बीएपी के उभार के बाद इस वोट बैंक में बंटवारे की स्थिति पहले ही दिखाई दे चुकी है. निकाय चुनाव में बीएपी का विस्तार कांग्रेस के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है. खासकर उन वार्डों में जहां आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, वहां बीएपी की मौजूदगी कांग्रेस के पारंपरिक वोट में सेंध लगा सकती है. हालांकि इसका फायदा सीधे भाजपा को मिलेगा, यह भी तय नहीं है. यदि बीएपी कांग्रेस के साथ भाजपा के वोट बैंक में भी सेंध लगाती है तो कई निकायों में मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो सकता है.

छात्र राजनीति से दिल्ली की सत्ता तक पहुंचीं रेखा गुप्ता

कई बड़े नेताओं ने यहीं से शुरू किया सियासी सफर

नई दिल्ली, 8 सितंबर. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव भले ही विश्वविद्यालय परिसर में होते हों, लेकिन इनका असर दिल्ली की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक दिखाई देता रहा है.

वर्ष 1954 में शुरू हुए इस चुनावों ने पिछले सात दशकों में अलग-अलग विचारधाराओं के नेताओं को राजनीतिक मंच दिया. यहां से निकले कई छात्र नेताओं ने आगे चलकर पार्षद, विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया. इस लिहाज से डूसू को दिल्ली और राष्ट्रीय राजनीति के लिए नेतृत्व तैयार करने वाली प्रयोगशाला कहना गलत नहीं होगा.

चुनाव भले ही परिसर में होते हों, पर इनका असर राष्ट्रीय स्तर तक दिखाई देता है इस प्रयोगशाला से निकली सबसे अहम राजनीतिक उपलब्धि दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं. वह डूसू सचिव रहने के बाद वर्ष 1996-97 में अध्यक्ष बनी थीं. छात्र राजनीति से निकलकर उन्होंने नगर निगम की राजनीति में कदम रखा और तीन बार पार्षद रहीं. वर्ष 2025 में शालीमार बाग से विधायक चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री बनीं. डूसू के इतिहास में यह पहला मौका है, जब यहां की छात्र राजनीति से निकला कोई नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा. दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी वर्ष 1988-89 में डूसू अध्यक्ष रहे थे.

जेटली, माकन और गोयल ने अहम जिम्मेदारियां संभाली

डूसू ने ऐसे नेताओं को भी तैयार किया, जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं. वर्ष 1974 में एबीवीपी के टिकट पर अध्यक्ष बने अरुण जेटली आगे चलकर राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री बने. वर्ष 1986 में डूसू अध्यक्ष रहे अजय माकन केंद्र सरकार में मंत्री बने. वर्ष 1978 में अध्यक्ष रहे विजय गोयल तीन बार लोकसभा और एक बार राज्यसभा सदस्य रहे तथा केंद्र में मंत्री की जिम्मेदारी संभाली.